ऐसे लोगों को, जिनके लाइसेंस खो गए हैं, रेडियो लाईसेंस बनवाने की सुविधा दी थी);

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पुन: इस प्रकार की सुविधा देने का विचार है जिससे डाक तार विभाग को राजस्व प्राप्त हो सके, और

(ग) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां । इस तरह की माफी पिछली बार वर्ष 1970 में दी गई थी ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव डाक तार बोर्ड या सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'विशेष रोजगार योजना' के दौरान के कार्यान्वयन के लिये बिहार को निधियों की व्यवस्था करने में विलम्ब

*492. श्री रामावतार शास्त्री : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य को निर्धारित राशि न मिलने के कारण राज्य के किसी भी जिले में 'विशेष रोजगार योजना' (स्पेशल एम्प्लाईमेंट स्कीम) कार्यान्वित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित राशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Special Quota of Cement for Major Projects in Maharashtra

*493. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the cement received from Bagalkot Cement factory was sub-standard;

(b) If so, whether the Maharashtra Government had to postpone the completion programme of Koyana Project by about one year thereby causing a loss of about Rs. 75,000 per day to the State Government;

(c) whether Government will allot special cement quota for the major projects; and

(d) if not, whether Government would allow the State Government to import required quantity of cement?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) According to sample test conducted by the National Test House, Bombay, the cement produced at Bagalkot Cement factory conformed to the specifications prescribed by the Indian Standard Institution.

(b) Does not arise.

(c) The request for special quota, as and when received from the Government of Maharashtra, will be given due consideration.

(d) As the present shortage of cement is essentially a result of the power cut and as the same is being restored now, the production is expected to pick up. The import of cement is not considered necessary.